(a) what are the recommendations made by the Committee set up by the Planning Commission to go into the problem of growing expenditure on O & M;

(b) the Government's reaction thereto; and

(c) whether Government would take States into confidence before implementing any of the recommendations?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) No Committee has specially been constituted by the Planning Commission to go into problem of growing expenditure on O & M of irrigation projects. Under the Constitution, irrigation being a "State Subject" the responsibility for investigation, formulation, execution as also Operation and Maintenance primarily rests with the concerned State/U.T.

Impact on Employment Generation under Economic Liberalisation

1878. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the all-round economic liberalisation during the last two years has not made a significant impact on employment generation;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the number of unemployed persons has, thus, increased by 1.5 million during this period;

(d) if so, what are the reasons for this alarming situation;

(e) whether it is also a fact that the employment growth during the first two years of the Eighth Five Year Plan, coinciding with the liberalisation period has been lower than the modest target of 8.5 million new jobs per year during the Eighth Five Year Plan period;

(f) if so, what are the reasons therefor; and

(g) what steps Government have taken to ensure that the target of creating jobs for 43 million people during the Eighth Plan period is not missed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (g) Open unemployment at the beginning of the Eighth Five Year Plan (1992-97) was estimated to be 17 million. The estimated unemployment at the end of 1993-94 is 18.5 million. During the first two years of the Eighth Plan, employment is expected to have grown by 6 million per year on an average as against the target of 8.5 million per year during the Plan period. The lower estimated average growth rate is mainly due to lower growth rate of Gross Domestic Product (GDP) than the envisaged rate of 5.6% during this period. The rate of growth of employment in the first two years of Plan has been, on the average higher than the average rate of growth of employment during the period 1985—92. Employment intensity of economic growth has also been higher during the first two years of the Plan period 1985—92. As a result of the ongoing economic reforms the economy is expected to grow at a higher rate and with improved employment and the intensity. This is expected to ensure the realisation of the employment goals of the Eighth Plan.

सातवीं योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए लोग

1879. **श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवी पचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए कुल कितना योजना परिव्यय निर्धारित किया गया था;

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ऐसे लोगों अथवा परिवारों की राज्यवार अनुमानित संख्या कितनी थी जिन्हे उक्त अवधि के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर लाया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितने श्रमदिवसों का सृजन किया गया?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवी पचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय **विवरण-I (नीचे देखिए)** में दिया गया है।

(ख) प्रत्येक पाच वर्ष में गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार 1983-84 तथा 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियो की राज्यवार संख्या विवरण-II **(नीचे देखिए)** में दी गई है।

(ग) सातवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के तहत सृजित रोजगार से सहायता प्राप्त परिवारों की राज्यवार संख्या विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय के संबंध में विवरण

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	कार्यक्रम	कुल परिव्यय (आवण्टन)
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)	3000.27
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)	2942.87
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०)	2545.02
4.	जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)	2630.67
	जोड़ :	11118.83

विवरण-II

1983-84 तथा 1987-88 के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों (ग्रामीण तथा शहरी-संयुक्त) की राज्यवार अनुमानित संख्या

(सरकार द्वारा जारी आंकड़े)

राज्य/संघ राज्य	1983-84	राज्य/संघ राज्य	1987-88
आन्ध्र प्रदेश	205.1	आन्ध्र प्रदेश	195.7
असम	49.8	असम	52.9
बिहार	365.5	बिहार	336.4
गुजरात	87.6	गुजरात	73.3
हरियाणा	21.7	हरियाणा	18.2
हिमाचल प्रदेश	6.1	हिमाचल प्रदेश	4.5
जम्मू और कश्मीर	10.3	जम्मू और कश्मीर	9.8
कर्नाटक	137.6	कर्नाटक	136.5
केरल	71.5	केरल	49.0
मध्य प्रदेश	254.9	मध्य प्रदेश	224.9
महाराष्ट्र	232.0	महाराष्ट्र	214.1
मणिपुर	1.9	उड़ीसा	135.1
मेघालय	4.0	पंजाब	13.9
उड़ीसा	118.1	राजस्थान	99.5
पंजाब	24.4	तमिलनाडु	176.9
राजस्थान	126.2	उत्तर प्रदेश	448.3
तमिलनाडु	202.2	पश्चिम बंगाल	173.5
त्रिपुरा	5.1	छोटे राज्य और संघ राज्य	14.2
उत्तर प्रदेश	530.6		
पश्चिम बंगाल	225.1		
नागालैंड और सभी संघ राज्य	32.3		
अखिल भारत :	2710.0	**अखिल भारत :**	2376.7

विवरण-III

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वास्तविक उपलब्धि के संबंध में विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई०आर० डी० पी० सहायता दिए गए परिवारों की संख्या	एन०आर० ई०पी०	आर०एल० ई०जी०पी०	जे०आर० वाई०
		लाख मानव दिवसों में सृजित रोजगार		
आंध्र प्रदेश	1253981	1107.23	1082.77	727.43
अरूणाचल प्रदेश	55555	8.36	4.81	7.25
असम	309324	156.41	123.71	122.51
बिहार	2534256	1686.59	1298.69	907.31
गोवा	13772*	10.82	8.09	8.62
गुजरात	636635	511.13	335.74	202.93
हरियाणा	266158	78.42	67.66	34.13
हिमाचल प्रदेश	158724	83.84	65.53	37.86
जम्मू व कश्मीर	137852	132.34	48.23	52.19
कर्नाटक	750655	793.25	759.37	407.56
केरल	486615	437.87	350.77	231.79
मध्य प्रदेश	1764509	1496.45	1014.85	932.24
महाराष्ट्र	1221195	1008.4	1010.78	795.93
मणिपुर	37131	22.14	9.80	10.50
मेघालय	29423	12.86	8.72	4.02
मिजोरम	26935	5.72	15.86	4.79
नागालैंड	26180	14.63	14.06	20.29
उड़ीसा	1095462	735.85	675.04	517.63
पंजाब	356181	87.86	77.76	34.23
राजस्थान	869638	1894.09	542.99	443.77
सिक्किम	10755	12.64	11.14	6.28
तमिलनाडु	1223646	1396.87	1229.91	910.81
त्रिपुरा	90836	46.81	36.65	19.53
उत्तर प्रदेश	3359465	2333.59	2124.13	1624.93
पश्चिम बंगाल	1398210	662.16	604.00	558.81
अंडमान और निकोबार द्वीप०	8602	11.39	4.96	3.08
चंडीगढ़	297	1.76	0.38	0.42
दादर व नगर हवेली	2987	6.65	4.09	3.04
दमन व दीव	18058	0.11**	—	1.08
दिल्ली	14649	2.71	3.27	2.30
लक्षद्वीप	2074	5.97	3.17	2.53
पांडिचेरी	18769	10.52	6.89	8.08
जोड़ :	18178529	14775.44	11543.82	8643.87

* वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के लिए गोवा के आंकड़े दमन में शामिल हैं।

** 1985-86 से 1987-88 तक के लिए दमन और दीव के आंकड़ों में शामिल हैं।

@ सातवीं योजना के प्रथम चार वर्ष अर्थात् 1985-86 से 1988-89 तक शामिल है।

@@ सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष अर्थात् केवल 1989-90 है।